प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-7 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 11-18 फरवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या वीरभद्र की कांग्रेस 2014 में मिली हार को पलट पायेगी

शिमला/शैल। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें वीरभद्र से छीन कर ले गयी थी बल्कि अपने संसदीय हल्के मण्डी से मुख्यमन्त्री होते हुए अपनी पत्नी की सीट तक वीरभद्र नही बचा पाये थे। 2014 की इस हार को मोदी लहर का परिणाम करार दिया गया था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में भी वीरभद्र कांग्रेस को पुन: सत्ता में नही ला पाये यह एक कड़वा राजनीतिक सच है। लेकिन आज राजनीतिक परिदृश्य फिर बदला हुआ है। 2014 की हार के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात और कर्नाटक में अपना प्रदर्शन सुधारने के बाद मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें बना ली हैं। अब भाजपा मोदी के पक्ष में 2014 जैसा वातावरण नही है। इसलिये प्रदेश के संद्धर्भ में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वीरभद्र की कांग्रेस प्रदेश में 2014 की हार का बदला ले पायेगी?आज प्रदेश की कांग्रेस को वीरभद्र की कांग्रेस कहा जा रहा है क्योंकि सुक्खु को हरवाना वीरभद्र के लिये एक मुद्दे की शक्ल ले चुका था। इसी परिदृश्य में जब वीरभद्र, आनन्द शर्मा, आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री ने हाथ मिलाया और राठौर के नाम पर लिखित में सहमति जताई तब यह बदलाव हुआ।

अब राठौर ने जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है उसमें भी इन्ही चारों नेताओं का पूरा-पूरा दखल माना जा रहा है। राठौर ने अब तक की सबसे बड़ी लम्बी कार्यकारिणी का गठन किया है। थोक में उपाध्यक्षों महासचिवों और सचिवों के पद बांटे गये हैं लेकिन इतनी बड़ी कार्यकारिणी पर इन बड़े नेताओं का कोई विरोध सामने नही आया है जबकि कुछ पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वाकायदा इतने ज्यादा पदाधिकारियों पर हैरत जताई है। यही नही प्रदेश कार्यकारिणी की तर्ज पर ही अब जिला और ब्लॉक ईकाईयों के गठन में भी उसी तर्ज पर पद बांटे जा रहे हैं। जबकि एक समय ऐसे बनाये गये पदाधिकारियों की पात्रता पर वीरभद्र ने यहां तक कह दिया था कि जो लोग पंचायत स्तर पंच का चुनाव नही जीत सकते उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारीयां दे दी गयी हैं। इसलिये आज जब वीरभद्र सहित सारे बड़े नेता इस सब पर चुप हैं तो स्वभाविक रूप से आज की प्रदेश कांग्रेस को राठौर की बजाये वीरभद्र की कांग्रेस कहना असंगत नही होगा। क्योंकि राठौर ने उस समय जिम्मेदारी संभाली है जब मार्च के प्रथम सप्ताह में तो लोस चुनावों के लिये आचार संहिता लग जायेगी। इतने समय में तो शायद पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर ईकाईयों का भी गठन न हो पाये। लोस चुनावों के लिये ईच्छुक उम्मीदवारों के आवदेन आने के बाद उनके नाम आगे भी प्रस्तावित कर दिये गये हैं। इनके बाद और नामों की भी सूची मांग ली गयी है और हाईकमान अपने ही सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी यह माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो हाईकमान की भेजी हुई दो टीमों ने प्रदेश का सर्वे किया है और इस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा यह माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सुक्खु को भी इसी सर्वे के आधार पर हटाया गया था। क्योंकि सर्वे में यह कहा गया था कि सुक्खु की अध्यक्षता में वीरभद्र और उसका पूरा खेमा चुनावों में काम नही करेगा। वीरभद्र ने जिस तरह से हमीरपुर से राजेन्द्र राणा के बेटे और कांगड़ा से सुधीर शर्मा की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। उस पर प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की थी। उसके बाद वीरभद्र ने मण्डी से अपनी उम्मीदवारी को लेकर यह ब्यान दिया था कि यदि हाईकमान आदेश करेगा तो वह चुनाव लड़ लेंगे। वीरभद्र के ब्यानों का हाईकमान द्वारा संज्ञान लेने के बाद सुक्खु को अभी बदलने का फैसला हुआ था। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिये हाईकमान ने आनन्द शर्मा की जिम्मेदारी लगायी और फिर आनन्द शर्मा ने इन अन्य नेताओं को विश्वास में लेकर इस बदलाव को अजांम दिया।

इस बदलाव के बाद जब राठौर राहुल गांधी से मिलने गये थे तब उन्हें चुनावों के मद्देनजर संगठन में इन नेताओं के सारे विश्वस्तों को स्थान देते हुए पुराने लोगों को भी यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये थे। इन्ही निर्देशों के कारण सुक्खु काल के लोगों को हटाया नही गया है। इस वस्तु स्थिति में यह माना जा रहा है कि लोस चुनावों की पूरी जिम्मेदारी वीरभद्र और मुकेश अग्निहोत्री पर आने वाली है। क्योंकि हाईकमान इस बार एक-एक सीट को लेकर गंभीर है। सर्वे के आंकलन को माने तो उसमें यह सुझाया गया है कि यदि वीरभद्र जैसे बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा जायेगा तो वह ईमानदारी से सरकार के प्रति आक्रमकता निभायेंगे और उसी के साथ सारी खेमे बाजी भी अपने आप खत्म हो जायेगी। क्योंकि जब बड़े नेताओं के सिर पर सीधे जिम्मेदारी आ जाती है तब वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं।

सूत्रों की माने तो हाईकमान ने वीरभद्र के बेटे की शादी में व्यवस्तता के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है यह संकेत दे दिया गया है कि मण्डी से वीरभद्र परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव में उतरना होगा। हिमाचल का चुनाव मई के अन्तिम फेज में होगा और वीरभद्र शादी की व्यवस्तता से मार्च में ही फ्री हो जायेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री और सुखविन्दर सिंह सुक्खु में से कोई उम्मीदवार होगा। इसी तहर कांगड़ा से सुधीर, जी एस बाली, आशा कुमारी और विजय सिंह मनकोटिया में से कोई उम्मीदवार होगा। शिमला से धनी राम शांडिल, विनोद सुल्तान पुरी और सोहन लाल के नाम सर्वे में सुझाये गये हैं। माना जा रहा है कि इन बड़े नेताओं को भी इसके संकेत दे दिये गये हैं। इस परिदृश्य में राठौर के लिये एक बड़ा काम पूराने नेताओं की पार्टी में वापसी करवाना है और वह इस काम में लग भी गये हैं। माना जा रहा है कि लोस चुनावों की गंभीरता को देखते हुए पार्टी से बाहर निकाले गये सारे नेताओं को देर सवेर वापिस लिया जा रहा है और लोस चुनावों के बाद संगठन के आकार-प्रकार पर नये सिरे से विचार विमर्श किया जायेगा। अभी लोस चुनावों से पूर्व पार्टी में प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी किसे दी जाती है इस पर मन्थन चल रहा है क्योंकि इन चुनावों में प्रवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी इसलिये अभी तक राठौर की कार्यकारिणी में प्रवक्ता का पद खाली रखा गया है।

प्रदेश का कर्जभार पंहुचा 52000 करोड़

शिमला/शैल। इस बार बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के ही विधायक पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर का सवाल था कि 15 जनवरी 2019 तक जयराम सरकार ने कितना कर्ज लिया है। इस सवाल के जवाब में बताया गया कि 3451 करोड़ का कर्ज लिया गया और इसमें 3000 करोड़ खुले बाजार से लना पड़ा है। इसी के साथ यह भी बताया गया कि इसमें सरकार ने कुछ कर्ज वापिस भी कर दिया है और इस तरह शुद्ध रूप से केवल 1838.75 करोड़ का ही ऋण लिया गया है। मुकश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकार की कर्ज लेने की सीमा 4524 करोड़ है और सरकार का कुल कर्ज 4975.45 करोड़ है। लेकिन मुख्यमन्त्री ने अपने बजट भाषण में सदन को बताया है कि इस वर्ष 5068 करोड़ का ऋण लेना पड़ेगा। मुख्यमन्त्री के बजट भाषण के आंकड़ों को सही मानते हुए कुल कर्ज 52000 करोड़ से ऊपर चला जाता है। कर्ज का दस्तावेज 2003 से 2017-18 तक का शैल के पिछले अंक में पाठकों के सामने रखा जा चुका है।

कर्ज को लेकर सदन में आये राम लाल ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के प्रश्नों पर चर्चा नही हो पायी है और इस तरह यह सरकार का लिखित जवाब ही रह गया है। लेकिन बजट भाषण पर हुई चर्चा में कर्ज की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। मुख्यमन्त्री ने इस चर्चा का जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि पूर्व में कर्ज लेकर मौज मस्ती होती रही है। मुख्यमन्त्री का यह आरोप कितना सही है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या जयराम सरकार इस बढ़ते कर्जभार का रोकने का कोई ठोस उपाय कर रही है? जयराम पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं इस नाते उनका दामन कर्ज करने के दाग से साफ था। ऐसे में यदि वह प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर कोई श्वेतपत्र ले आते तो प्रदेश की जनता उनके कथन पर आसानी से विश्वास कर लेती। लेकिन वह कर्ज के लिये जिम्मेदार अफरशाही के हाथों में ऐसे खेल गये कि यह श्वेत पत्र नही ला सके। जबकि 1998 में धूमल यह श्वेतपत्र लेकर आये थे और इसी कारण से वह वीरभद्र शासन पर लगातार भारी पड़ते रहे।

अभी जो आंकड़े अफसरशाही ने मुख्यमन्त्री के सामने परोसे हैं उनमें अपने में अन्त विरोध है। सवाल के जवाब में कुछ है और बजट भाषण में कुछ। फिर बजट की विवरणिका में जो पूंजीगत प्राप्तियों का सकल ऋण कहा गया है वह क्या है इस पर कोई स्पष्टीकरण नही आ पाया है। भारत सरकार मार्च 2016 में भी कर्ज को लेकर चेतावनी पत्र भेज चुकी है। लेकिन इस पत्र पर कोई अमल नही हुआ है। क्योंकि एफआरबीएम अधिनियम की धारा दस के तहत अधिकारियों को यह छूट हासिल है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कारवाई नही की जा सकती है।

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the state government or any of its officers, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made there under. लेकिन इसी अधिनियम की धारा 7(2) में सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह अपने संसाधन बढ़ाये Whenever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the state Government that affects either the State Government or its public sector undertakings, the State Government, prior to taking such policy decision, shall take measure to fully offset the fiscal impact for the current and future years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the consolidated Fund of the State under any Act enacted by Legislative Assembly to provide for the appropriation of such sums , or by taking interim measure fro revenue augmentation, or by taking up a combination of both.

लेकिन एफआरवीएम के इन प्रावधानों के तहत क्या संसाधन बढ़ाने की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है शायद नही। केवल हर बार हर मुख्यमन्त्री के नाम से हर बजट में ऐसी घोषणाएं कर दी जाती हैं जिनको पूरा करने के लिये केवल कर्ज लेना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश 52000 करोड़ के कर्ज तले डूबा है। इसी कारण से आज हर काम आऊटसोर्से पर किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती को अपनाने का उचित समय:आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने देश के किसानों को अपनी आय को दोगुना करने के लिए केवल प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण व पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल हरियाणा के ज़िला कैथल के पुंडरी में बुद्ध राम ढल्ल जल कल्याण समिति, पुंडरी द्वारा प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि कुरूक्षेत्र के गुरूकुल में कई वर्षों तक रासायनिक व जैविक कृषि करने के बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, जिसमें देसी गायों के उपयोग से कृषि उपज को शून्य लागत पर बढ़ाने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के तहत किसानों को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नही है तथा इससे बंजर भूमि पुन: उपजाउ बनाने के अतिरिक्त पानी के न्यूनतम उपयोग की आवश्यकता रही है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के अत्याधिक उपयोग पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इनका प्रयोग न केवल फसलों के पोषक तत्वों को कमजोर कर रहा है बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान रासायनिक खेती के कारण कैंसर और मधुमेह जैसी कई बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस कारण प्राकृतिक खेती को अपनाने का यह उचित समय है, ताकि उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त प्राकृतिक खेती के कई अन्य लाभ हैं क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरकता और भू-जल स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायक है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही यह चेनावती दे दी है यदि हम आज जल संसाधनों, मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण के विषय में नही सोचेंगे तो दो दशकों के बाद पानी की भारी कमी के कारण भूमि बंजर हो जाएगी, इसलिए यह उचित समय है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।

उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती तेजी से बढ़ रही है और लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के किसानों ने प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाया है तथा राज्य सरकारें उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरूकुल कुरूक्षेत्र भी किसानों को शिक्षित करने और प्राकृतिक खेती से सम्बन्धित प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान कर रहा है।

उन्होंने प्राकृतिक खेती के तरीकों के विषय पर विस्तार से जानकारी दी और किसानों को प्राकृतिक खेती पर अपनी पुस्तक भी भेंट की।

राज्यपाल ने इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी।

बुद्ध राम ढल्ल जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जगदीप ढल्ल ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्यपाल को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया।

पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले की हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने की कड़ी निंदा

शिमला/शैल। जम्मू-कश्मीर में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के अब तक 44 जवान शहीद हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा सहित तमाम पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल संवेदना व्यक्त करता है और दुख प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में कांग्रेस सेवादल का एक एक सदस्य जवानों के परिवारों के साथ है। उनके परिवारों की वेदना हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल अच्छी तरह समझता है। इस शोक की घड़ी में सांत्वना के शब्द पर्याप्त नहीं होते, फिर भी शहीद परिवार के पीछे न केवल कांग्रेस सेवादल बल्कि पूरा देश खड़ा है।

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ अब तक शहीद हुए जवानों के प्रति अनुराग शर्मा ने कहा कि पुलवामा 'जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो गहरी चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल केन्द्र सरकार से मांग करता है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। प्रदेश मुख्य संगठन ने आरोप लगाया, उरी, पठानकोट, पुलवामा हमले दर्शाते हैं कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि आज के दिन सारी राजनीत व आपसी द्वेश छोड़ उन महान लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह के कायराना आतंकी हमले में दुनिया के सबसे जाबाज शहीदों का इस तरह से जाना देश के लिए पीड़ादायक और गम्भीर विषय है। हम सबको इसका प्रतिकार कई गुणा ताकत से देना होगा। अब समय आ गया है कि सभी देशवासियों को एकजुट होकर पुलवामा कांड की निंदा करनी चाहिए तथा सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह ऐसी कायरता पूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके और इसके पीछे जो भी ताकत है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें अब भी यदि सरकार ने कारवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर हमारे सैनिकों का मनोबल घटेगा और यह किसी भी तरह देश हित में नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल इन सब शहीद सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता है तथा सभी घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना हम ईश्वर से करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मैं चेतावनी देना चाहता है कि अपनी कायराना हरकतों से बाज आ जाए वरना उसको याद रखना चाहिए कि हमारी सेनाएँ सन् 1971 की पुनरावृत्ति करने का भी साहस रखती है।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवानों की मौत पर राज्यपाल ने जताया शोक

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में हुए एक बड़े आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है।

इस आतंकी हमले से आहत राज्यपाल ने राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए राजभवन में शुक्रवार शाम को आयोजित होने वाले रात्रि भोज के आयोजन को रद्द कर दिया है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदस्यों के सम्मान में प्रत्येक बजट सत्र के दौरान रात्रि भोज का आयोजन करते है।

लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हो:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव न करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि लड़की परिवार का गौरव है तथा उच्च पदों पर सेवारत होकर उनका राष्ट्र के समग्र विकास व समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है।

राज्यपाल हरियाणा के जिला कैथल के कमालपुर में ज्ञानदीप सामाजिक एवं कल्याण सोसायटी द्वारा आयोजित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा देने से सामाजिक आर्थिक बदलाव आते है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देशों के संविधान में महिलाओं तथा पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किए गए है। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने से उनके सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलेगी और वे देश की समृद्धि और विकास में अपना योगदान दे सकेंगी।

राज्यपाल ने कहा कि समाज में नशे की बुरी लत एक बड़ी चुनौती बन कर सामने आई है ऐसे में अभिभावकों तथा अध्यापकों का यह दायित्व बनता है कि वे युवा पीढ़ी को इस बुराई के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करें और उनकी ऊर्जा को समाज की बेहतरी के लिए उपयोग लाने में सहायता करे।

उन्होंने किसानों से रासायनिक खादों का उपयोग न करने तथा अपनी आय को दोगुना करने व भूमि की उर्वरता व भू-जल स्तर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने क्षेत्र ग्रामीण विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने तथा खेल व अन्य गतिविधियों की और प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञानदीप अकादमी की सराहना की।

राज्यपाल ने इस अवसर पर समाज में योगदान देने के लिए विभिन्न व्यक्तियों व प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

आंतकी हमले में हुए शहीदों की शहादत को प्रणाम: धूमल

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पुलवामा आंतकी हमले में अपने प्राण देश के लिए न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को प्रणाम करते हुए कहा है कि आंतकियों द्वारा किया गया यह हमला एक कायरता पूर्ण कृत्य है जिसकी में कड़ी आलोचना और भर्त्सना करता हूँ। प्रो. धूमल ने हमले शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजली अर्पित करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है तथा प्रार्थना कर रहा है कि शोकग्रस्त परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में धैर्य और साहस प्रदान करें। प्रो. धूमल ने आंतकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों के परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रो. धूमल ने हमले में घायल हुए सैनिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rates tenders on form No. **6 & 8 are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of H.P** for the following works from registered PWD contractors. The tenders should reach this office on or before **05-03-2019 up to 10.30 A.M** and shall be opened on the same day at **11.00 A.M** in the presence of tenderers or their authorized representative who wish to be present. The telegraphic and conditional tenders shall not be accepted. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non refundable) up to **02.03.2019 till 3.00 p.m.**

The earnest money in the shape of National Saving certificates/time deposit/saving account in any of the post office saving bank account in H.P duly pledged in favour of **Executive Engineer Mechanical Division HP PWD Kullu** must accompany each tender. The tender received without proper earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject the tender without assigning any reasons. If holiday falls on date of opening of tender it will be opened on next working day.

Sr.No. Name of Work	Amount put to tender	Cost of tender form	Earnest Money	Time allowed
1. Repair of 50.00 feet span SSR bailey bridge at Chhakki Nallah in Distt. Kullu H.P. (Sh:- Providing and fixing , fabrication of steel deck unit)	3,92,190/-	350/-	7850/-	One month

TERMS AND CONDITION
1. Copy of sale tax number must also accompany with application for purchase of tender form.
2. The rate shall be valid up to 120 days.
3. Income tax as per rule and royality as per HP Govt. rules GST @ 2% will also be deducted from the bill .
4. Conditional/telegraphic tenders are not acceptable.
5. Tender received after due date and time shall not be entertained.
6. The payment of the job shall be released only after completion of work and 10% security will be Released After 6 months duly certified by the Engineer-in-Charge.

Adv. No.-4654/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the form NO 6 &8 are invited by the **Executive Engineer Nalagarh Division HP PWD Nalagarh on behalf of the Governor Of Himachal Pradesh** From the approved and eligible contractors enlisted in **HP PWD,** in the appropriate class for the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative.

Time schedule of tender:-
(1)The last Date & time of receipt of Application for tender Form 05-03-2018 up to 11.00 AM.
(2) The last date of issue of tender form: 05-03-2019 up to 4.00 P.M
(4) The date of opening of tender: 06-03-2019 at 11.00 A.M

Earnest money in the shape of National Saving certificate/ Time Deposit accounts/ Saving accounts in any of the Post Office/ Bank in H.P duly pledged in favour of the **Executive Engineer, HP PWD Nalagarh must be accompanied with the tender documents.**

The conditional tender and the tender received without earnest money will be summarily rejected. The **Executive Engineer reserves right to accept or reject any or all tenders ,the tenders shall be kept open for 120 days.** The contractor should be registered as dealer **Under HP VAT/ sale Tax Act 1968** and also produce sale tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	E/ Money	Time	Cost of Form
1. A/R & M/O various road under Nalagarh sub division (SH repair to pot hole in (joghon section)	497382	10,000	One month	350
2. A/R & M/O various road under Nalagarh sub division (SH repair to pot hole in (joghon section)	4,97,382	10,000	One month	350

Following documents should accompany the application for tender:-
1. The tender forms will be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory .
2. Earnest money should be accompanied with application without earnest mony will not be entertained.
3.The photo copy of G.S. T No /Vat/ EPF/Enlistment Number should be attached with application otherwise tender form will not be issued.
4. The contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand.

Adv. No.-4655/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने शहीद तिलक राज को अंतिम विदाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने श्रद्धा में हाथ जोड़कर और पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर सीआरपीएफ के जवान शहीद तिलक राज जो इस महीने की 14 तारीख को

पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए है, को अंतिम सम्मान देने में राज्य का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र में पैतृक गांव जंद्रो जाकर तिरंगे में लिपटे शहीद तिलक राज के ताबूत पर माल्यार्पण कर उनको अंतिम सम्मान दिया।

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन द्वारा टक्कर मारने के परिणामस्वरूप सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और पांच अन्य घायल हो गए।

मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता श्री लायक राम, माता, पत्नी और शहीद के परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद तिलक राज ने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुःख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ है तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

शहीद तिलक राज की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में हुई जिसमें मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भाग लिया।

शहीद के भाई बलदेव सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी।

ग्रामीणों ने 'शहीद तिलक राज अमर रहे' और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा सैनिकों की हत्या कायरतापूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस प्रकार के नापाक इरादों को सफल नहीं होने देगा और देश पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त शहीद की पत्नी को सरकारी रोजगार सहित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व सीएम और सांसद शांता कुमार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार,और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद को सम्मान दिया।

कमजोर वर्गों के उपचार के लिए प्रदेश में शुरू होगी सहारा योजना:विपिन परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2019-20 के राज्य बजट को सभी वर्गों का हितैषी करार दिया है। इस बजट में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 2,482 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे प्रदेश के सभी वर्गों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजो को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से 'सहारा योजना' आरंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कैंसर, पारकिनसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया और रेनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 4200 मरीज एच.आई.वी/एड्स से पीड़ित हैं। इस रोग से संक्रमित मरीजों के भत्ते को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा इन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

विपिन परमार ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल में सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 12 स्वास्थ्य संस्थानों को संपूर्ण अस्पताल बनाया जाएगा जिनमें कुछ जिला अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इन अस्पतालों में हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा रेफर किए गए मरीजों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग का भी प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्रेस्ट व सरवाईकल कैंसर की जांच व ईलाज के लिए मोबाईल डायगनोस्टिक वैन तैनात की जाएगी। यह मोबाइल वैन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर इन बीमारियों को रोकने के लिए कार्य करेंगी।

अन्य राज्यों के लिए आदर्श हिमाचल विधानसभा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई-विधान प्रणाली को लागू करने वाली पहली अत्याधुनिक कागज रहित विधानसभा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा अन्य राज्यों के लिए आदर्श है और उन्हें भी इस प्रणाली को अपनना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने

विधायी प्रारूपण और लोकसभा के अधिकारियों के 34वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण लोकसभा ब्यूरो, भारतीय तकनीकी और इंडियन टेकनिकल और ईकोनोमिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया जिसमें 27 देशों के लगभग 43 प्रतिनिधि भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पर सरकार के भारी खर्च को बचाने और विधानसभा सत्र के दौरान वाहनों को अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा की गई यह पहल अत्यंत सराहनीय है। ई-संविधान प्रबंधन का कार्यान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग करने से विधानसभा के सदस्यों के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं और कार्यक्रम राज्य की विधान सभा के कामकाज को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बेहतर ढंग से समझने में बहुत कारगर साबित होते है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई पूर्व-संवैधानिक इतिहास नही है क्योंकि यह राज्य स्वतंत्रता के उपरांत गठित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य पहली बार 15 अप्रैल 1948 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया और 25 जनवरी, 1971 को भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। आज हिमाचल प्रदेश देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में एक है और निस्संदेह सबसे प्रगतिशील पहाड़ी राज्य है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा, न्यायिक अकादमी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान और हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के साथ एक संबद्ध कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रतिभागी न्यायिक अधिकारी, कानूनी सलाहकार, विधानसभाओं के अधिकारी और दक्षिण सूडान से संसद सदस्य हैं। लोकसभा सचिवालय के सचिव पुनीत भाटिया ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

महेंद्र सिंह ने दिये आईपीएच की सभी परियोजनाओं के काम में तेजी लाने निर्देश

शिमला/शैल। सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग की चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए विभाग के प्रदेश भर से आए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना का सपना है तथा इन परियोजनों से जल संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं जल संसाधनों को सुदृढ़ पर केंद्रित होगी तथा राज्य की छोटे और सीमांत किसानों की आय में स्थायी बढ़ौतरी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने राज्य में विश्व बैंक से वित्त पोषित हाईड्रोलोजी परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन शाह नहर, सिद्धाता, फिन्ना सिंह, स्वां नदी तटीकरण, छोंच खडड् सहित चल रही परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिए।

जय राम सरकार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मिले सैटेलाइट फोन

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) और वित्त आयुक्त (राजस्व) मनीषा नंदा ने आयोजित बैठक में राज्य के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सैटेलाइट फोन सौंपे।

उन्होंने कहा कि आपदा के समय संचार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट फोन विशेष कर राज्य के जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों मे आपदा प्रबंधन में बहुत उपयोगी साबित होंगे। मनीषा नंदा ने कहा कि सैटेलाइट फोन अगले चरण में उपमण्डल स्तर पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की पहल पर ही ये सैटेलाइट फोन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में राज्य के विभिन्न जिलों में 15 वेरी समॉल अपर्चर टरमिनल (वीसैट) भी लगाए जाएंगे।

विशेष सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डी. सी. राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर सैटेलाइट फोन के प्रयोग के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य पुस्तकालय का उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा के निकट

केनेडी चौक में 10 करोड़ की लागत से निर्मित भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर राज्य पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले इस पुस्तकालय में लगभग 120 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य पुस्तकालय में 72,400 पुस्तकों का समृद्ध संग्रह होगा जो छात्रों, शोधार्थियों तथा आम लोगों के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पुस्तकालय का उद्घाटन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हांलाकि इस भवन का अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपये थी जबकि इस पर 10 करोड़ की लागत आई है जिसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग की सराहना की। इस भवन में पुस्तक के स्थान के अतिरिक्त, अध्ययन कक्ष, पटल, लाइब्रेरियन कक्ष, पुस्तकों को पुस्तकालय से निकालने व जमा करने का कक्ष, कम्प्यूटर अनुभाग, डिजिटलाइजेशन अनुभाग, तकनिकी अनुभाग, कैंटीन, बाइडिंग क्षेत्र, सर्वर कक्ष और बिजली कक्ष आदि होंगे।

बर्फबारी और वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी प्रभावित जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बर्फबारी और वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। अग्रवाल ने सड़क, बिजली और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में स्थिति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने चंबा, मंडी, शिमला, किन्नौर और कुल्लू के उपायुक्तों को जल्द से जल्द अपने जिलों में बिजली आपूर्ति बहाल करने और विशेष रूप से जिलों के मुख्य सम्पर्क सड़कों को खोलने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने सड़कों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति तैनात करने का भी आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) मनीषा नंदा, विशेष सचिव एमपीपी और विद्युत, विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा, एमडी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड जे.पी. काल्टा, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विवेक शर्मा, विभिन्न जिलों के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया।

आतंकवाद का कोई धर्म नही है, आतंकवादियों का कोई धर्म नही है और वे किसी भी धर्म के मित्र नही हैं। "मनमोहन सिंह"

सम्पादकीय

सत्ता के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर खोजना होगा आतंक का हल

जम्मू – कश्मीर के पुलवामा में गुरूवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये हैं। पूरा देश इस कायराना हमले के बाद सदमे और आक्रोश में है। हरके इस घटना की निन्दा करते हुए यह सवाल पूछ रहा है कि यह सब कब तक चलता रहेगा? मोदी सरकार के शासन में आतंक की यह सत्रहवीं घटना है। उड़ी में 18 सितम्बर 2016 को हुई आंतकी घटना में सेना बीस जवान शहीद हो गये थे और भारत ने उसका जवाब देते हुए 20 सितम्बर 2016 को ही पाक सीमा में घुसकर सर्जीकल स्ट्राईक करके आतंकीयों के सात ठिकानों को नष्ट करते हुए 38 आतंकीयों को मार भी गिराया था। इस सर्जीकल स्ट्राईक को सरकार का बड़ा कदम माना गया था। इस स्ट्राईक के बाद यह दावा किया गया था कि आतंकी गतिविधियों को शह देने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जायेगा। लेकिन इस स्ट्राईक के बाद भी यह घटनाएं रूकी नही है। बल्कि अब एक सप्ताह पहले ही खुफिया ऐजैन्सीयों के अर्लट के वाबजूद यह घटना अपने में बहुत सारे सवाल खड़े कर जाती है। यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या जम्मू – कश्मीर को लेकर हमारी नीति सही भी है या नही।

हर आतंकी घटना के बाद उसकी निन्दा की जाती है और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया जाता है। टीवी चैनलों पर बहस चलती है और उस बहस में सेना के कई सेवानिवृत बड़े अधिकारियों को बुलाकर उनकी राय/प्रतिक्रिया ली जाती है। कई चैनल पाकिस्तान के पीरजादा तक की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस प्रतिक्रिया में आरोप – प्रत्यारोप लगाये जाते हैं जिनसे कोई परिणाम नही निकलता है केवल इसी धारणा को पुख्ता किया जाता है कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार भी यही हुआ है। इस बार सेना के कुछ विशेषज्ञों ने सेना के लिये खरीदे जा रहे उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों पर यह कहकर एतराज जताया है कि इससे सेना की तैयारीयों पर असर पड़ता है। शायद उनका इंगित राफेल पर चल रहे वाद विवाद की ओर था। लेकिन इस घटना पर जो प्रतिक्रिया केन्द्र के राज्य मन्त्री जितेन्द्र सिंह की आयी है उसमें पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। जितेन्द्र सिंह की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह इस घटना पर राजनीतिक सवाल उठा रहे थे। अभी अफजगुरू की फांसी की बरसी के मौके पर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया रही है शायद जितेन्द्र सिंह उस पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। क्या केन्द्रिय मंत्री की इस तरह की प्रतिक्रया इस मौके पर आनी चाहिये थी यह एक अपने में बड़ा सवाल है।

आज देश के सामने बड़ा सवाल यह है कि यह सब कब तक चलता रहेगा? और यह सवाल देश की सरकार से ही पूछा जायेगा। आतंक को पाकिस्तान समर्थन दे रहा है देश यह लम्बे अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक सच यह भी है कि पाकिस्तान इन घटनाओं को अंजाम देने के लिये हमारे ही युवाओं को इस्तेमाल कर रहा है। उन्हे ही आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के बाद हथियार और गोलाबारूद दिया जा रहा है। यह सब हम सुनते आ रहे हैं लेकिन इसे रोक नही पाये हैं। पिछले दिनों यह भी सामने आया है कि अब गोला बारूद की जगह पत्थरबाजी लेती जा रही है। इन पत्थरबाजों के खिलाफ सेना ने कारवाई भी की है। इस कारवाई पर जम्मू – कश्मीर के बड़े नेताओं डा. फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिएं भी आयी हैं। लेकिन क्या इन प्रतिक्रियाओं के तर्क का गुण दोष देश के सामने रखा गया। भाजपा के साथ अब्दुल्ला और महबूबा दोनों काम कर चुके हैं। महबूबा के साथ तो अभी भाजपा सरकार में भी भागीदार थी। लेकिन इस भागीदारी के बावजूद आज तक देश के सामने यह नही रखा गया कि आखिर जम्मू – कश्मीर की समस्या है क्या? वहां का युवा आतंकी क्यों बनता जा रहा है। वहां के नेतृत्व की इसमें क्या भूमिका है? उस भूमिका को सारे देश के सामने क्यों नही रखा जा रहा है? जब पाकिस्तान का ही हाथ इन घटनाओं के पीछे है तो फिर इसके खिलाफ आज तक कोई बड़ी राजनीतिक कारवाई क्यों नही की जा सकी है। जब पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव यूएन में आया था तब चीन ने उस पर वीटो की थी। आज चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत आगे है। देश के हर प्रदेश में चीन को काम मिला हुआ है। फिर हम चीन को इसके लिये सहमत क्यों नही कर पाये हैं कि वह इस मुद्दे पर भारत का साथ दे। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री के यहां एक समारोह में अचानक पहुंच गये थे। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी नेता से मुलाकात करके आये थे और यह चर्चा रही थी कि वह प्रधानमन्त्री के दूत बन कर गये थे। लेकिन इस सबका आखिर परिणाम क्या रहा? आतंकी घटनाएं बराबर जारी हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह कायम हैं।

यही नही भाजपा जनसंघ के समय से ही जम्मू – कश्मीर में धारा 370 का विरोध करती आयी है। यह उसका एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज केन्द्र में जिस प्रचण्ड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार रही है शायद आगे इतने बड़े बहुमत के साथ कोई सरकार न बन पाये। लेकिन इस सरकार ने धारा 370 हटाने के लिये कोई कदम नही उठाया। बल्कि जम्मू – कश्मीर के संविधान की धारा 35A के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिका पर केन्द्र सरकार का स्पष्ट पक्ष सामने नही आया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर केन्द्र सरकार अपना पक्ष स्पष्ट नही कर पायी है। नोटबंदी लाते हुए भी एक बड़ा तर्क यह दिया गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जायेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नही पाया है। इससे सीधे यह सवाल उठता है कि इस आतंकवाद की समस्या को राजनीति से ऊपर उठकर हल करने की आवश्यकता है। इसके लिये सारे राजनीतिक दलों को एक होकर इसका हल खोजना होगा। आज देश का कितना बड़ा बजट हमारी रक्षा तैयारियों पर खर्च हो रहा है और इन तैयारियों के नाम पर हम अत्याधूनिक हथियार व गोलाबारूद संग्रह करने के अतिरिक्त और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब भी यह हथियार और गोला बारूद चलेगा तो इससे केवल विनाश ही होगा यह तय है। ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की है कि समस्याओं को सत्ता के तराजू में तोलते हुए उन्हें आम आदमी के नजरिये से देखा जाये क्योंकि आम नागरिक की कहीं के भी दूसरे नागरिक से कोई शत्रूता नही होती है यह शत्रूता केवल राजनीतिक सत्ता की देन है और अब इससे ऊपर उठना होगा।

आधुनिक कोच फैक्ट्री (रायबरेली) "मेक इन इंडिया" का शानदार उदाहरण

- अगस्त 2014 में पहला कोच निर्मित किया गया था और तब से प्रति वर्ष इसका उत्पादन लगभग दोगुना हुआ
- वर्ष 2018 – 19 में 1,422 कोच उत्पादन की उम्मीद, जिनमें से अब तक 1,220 कोच निर्मित हो चुके
- भारतीय रेलवे की सभी उत्पादन इकाइयों की तुलना में एमसीएफ में उत्पादित कोच की लागत सबसे कम
- एमसीएफ में रोबोटिक्स, स्वचालन जैसी नई अवधारणाओं का व्यापक उपयोग किया जा रहा है
- उत्पादन बढ़ाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सेट भी यहां बनाने की योजना

आधुनिक कोच फैक्ट्री (एमसीएफ), रायबरेली की आधारशिला फरवरी, 2007 में रखी गई थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य मई 2010 में शुरू हुआ था। फैक्ट्री में 1,000 कोच निर्मित किए जाने थे। हालांकि, वर्ष 2011 से 2014 तक यहां कपूरथला से लाए गए कुछ कोचों का मामूली काम ही किया गया था। इस प्रकार 2011 से 2014 के बीच यहां केवल 375 कोचों का नवीनीकरण किया गया था, जबकि इसमें पूरी तरह से कोच का निर्माण किया जाना चाहिए था।

वर्ष 2014 के बाद से इस फैक्ट्री को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है। जुलाई 2014 में एमसीएफ को भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई घोषित किया गया। एक महीने के भीतर इसने पूरी तरह से निर्मित डिब्बों का उत्पादन शुरू कर दिया। तब से यहां प्रति वर्ष उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है: 2014 – 15 में 140 कोच, 2015 – 16 में 285, 2016 – 17 में 576, 2017 – 18 में 711 कोच निर्मित किए गए। वर्ष 2018 – 19 में 1,422 कोच के उत्पादन की उम्मीद है और अब तक 1,220 कोच निर्मित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर, 2018 को इस वर्ष उत्पादित 900वें कोच और एमसीएफ में निर्मित हमसफ़र रेलगाड़ी के रैक को रवाना किया था।

यह परिवर्तन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, समन्वय और सकेंद्रीत नेतृत्व से ही संभव हुआ है। बंद पड़ी मशीनों को शुरू किया गया। वर्ष 2013 – 14 में किए गए 33% सिविल कार्यों की तुलना में 2018 – 19 में 90% से अधिक सिविल कार्य पूर्ण किए गए। संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से आवंटित बजट का उचित उपयोग किया गया। 2013 – 14 में 45% राशि खर्च की गई थी, जबकि 2018 – 19 में 85% राशि व्यय की गई।

पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण एमसीएफ में अधिक कोचों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत में भी कमी आ रही है। भारतीय रेलवे की सभी उत्पादन इकाइयों में उत्पादित कोचों की तुलना में एमसीएफ में निर्मित कोच की लागत कम है। यह लाभ यात्रियों को दिया जाएगा और इससे अधिक सस्ती सेवाएं प्राप्त होंगी।

एमसीएफ 'मेक इन इंडिया' का शानदार उदाहरण है। एमसीएफ में रोबोटिक्स, स्वचालन जैसी नई अवधारणाओं का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

बजट 2018 – 19 में एमसीएफ की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1,000 कोच से बढ़ाकर वर्ष 2020 – 21 तक लगभग 3,000 कोच करने के लिए 480 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

एमसीएफ में निर्मित किए जा रहे नई पीढ़ी के सुरक्षित एलएचबी कोच रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। इस फैक्ट्री में हमसफर रेलगाड़ी के कोचों का उत्पादन भी शुरू किया गया है। एमसीएफ में स्मार्ट कोच भी बनाए गए हैं, जो बेहतर सुरक्षा और यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही भावी रखरखाव में सक्षम है। एमईएमयू, ईएमयू और मेट्रो कोच का भी उत्पादन यहां किया जाएगा। अगर सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो भविष्य में बुलेट ट्रेन के कोच भी एमसीएफ में निर्मित किए जा सकते हैं।

एमसीएफ में एल्यूमीनियम कोचों के निर्माण की भी योजना है, जो देश में इस तरह का पहला विनिर्माण होगा। स्टेनलेस स्टील के कोचों की तुलना में एल्युमीनियम कोच के कई फायदे हैं, जिनमें इनका हल्का वजन, अधिक सुंदर और कोच को टिकाऊ रखने की प्रति वर्ष कम लागत शामिल है। उत्पादन बढ़ाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सेट भी यहां निर्मित करने की योजना बनाई गई है।

एमसीएफ वर्ष 2020 – 21 तक शून्य ऊर्जा मेगा फैक्ट्री मानकों को पूरा करने वाली पहली रेल फैक्ट्री बन जाएगी। सौर ऊर्जा क्षमता 3 मेगावाट से बढ़ाकर 10 मेगावाट की जाएगी, जो इकाई और आबादी के लिए 'एनर्जी न्यूट्रल' मानक हासिल करने में सहायक होगी।

एमसीएफ से रायबरेली की स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए और आसपास के उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। वर्ष 2018 – 19 में सूक्ष्म,लघु और मझौले उद्यमों से 667 करोड़ रुपये का माल खरीदा गया। 2013 – 14 में रायबरेली की स्थानीय इकाइयों से खरीद 1 करोड़ रुपये से कम थी, लेकिन 2018 – 19 में अब यह 124 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, स्थानीय युवाओं को कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए गए हैं।

-पसूका-

.....और सत्ता कहती है जय हिन्द!

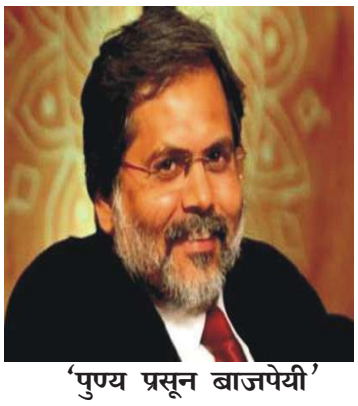

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

मेहुल चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड दी। उससे पहले जांच के लिये भारत लौटने से ये कह कर इंकार कर दिया था कि भारत में उनकी लिचिंग हो सकती है । विजय माल्या ने पहले भारतीय जेल को अमानवीय बताया और अब स्विस बैंक से कहा आप मेरे अकाउंट की जानकारी भारतीय जांच एंजेसी सीबीआई को कैसे दे सकते है जो खुद ही दागदार है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है । भारत के राष्ट्रीयकृत बैंको से जनता के पैसे को कर्ज ले कर ना लौटाने वाले कारपोरेट व उद्योगपतियों की कतार करीब 900 तक पहुंच चुकी है। और आंकडा बारह हजार करोड रुपये पार कर चुका है। इसी दौर में देश पर बढ़ता कर्ज 80 लाख करोड का हो चुका है। और आक्सफाम की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के टापमोस्ट सिर्फ नौ लोगो की आमदानी – कमाई या संपत्ति का कुल आंकडा देश के 65 करोड़ लोगो की आय संपत्ति या आमदनी के बराबर है। दुनिया में भारत को लेकर तमाम चकाचौंध बिखराने के बावजूद दुनिया भर से भारत के बाजार में डालर झौकने वाले बढ़ क्यो नहीं रह है ये सवाल अब भी अनसुलझा सा बना दिया गया है । 2017 में 40 बिलियन डालर का निवेश हुआ तो 2018 में 43 बिलियन जालर का निवेश भारत में हुआ। जबकि ब्राजिल सरीखे देश में 59 बिलियन डालर का विदेशी निवेश 2018 में हो गया। जंहा की सत्ता ने दुनिया घूमने पर सबसे कम खर्च किया। और चीन में 142 बिलियन डालर का निवेश 2018 में हो गया । तो भारत की दौड में किस देश से हो सकती है ये सोचने समझने से पहले इस हकीकत को भी जान लें कि यूपी में निवेश को लेकर जब योगी – मोदी ने बाइब्रेट गुजरात की तर्ज पर सम्मेलन किया तो निवेश का भरोसा देने वाले एक विदेशी कारपोरेट ने पिछले दिनो अध्ययन कर पाया कि कृर्षि अर्थव्यवस्था पर टिके यूपी में किसानों को अब अपनी फसल बचाने के लिये गाय के लिये बाड बनाने से जुझना पड रह है। और बाड लगाने क लिये किसानों के पास पैसे नहीं है और राज्य सरकार गायों की बढ़ती तादाद के लिये गौ चारण की जमीन तक की व्यवस्था तो दूर कोई व्यवस्था तक करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली की एक संस्था से मदद लेकर भारत के मेडिकल क्षेत्र में निवेश की योजना बनाने वाली विदेशी कंपनी ने पाया कि भारत में प्राइवेट अस्पताल खोलना सबसे फायदे का धंधा है। और सरकारी अस्पताल में न्यूनतम जरुरते तो दूर 70 फीसदी बीमार और ज्यादा बीमारी लेकर अस्पताल से लौटते है। यानी अस्पताल साफ सुधारे रहे सिर्फ ये काबीलियत ही प्राइवेट अस्पताल को लायक होने का तमगा दे देती है । फिर भारत काअनूठा सच शिक्षा से भी जुडा है जहां स्कूल जाने वाले 50 फीसदी से ज्यादा बच्चे जोड – घटाव तक नहीं कर सकते। अंग्रेजी तो दूर की गोटी है हिन्दी भी पढ नहीं पाते । यानी सामने वाला जो बोल रहा है उसे सुन कर जो सही गलत समझ में आये उसे ही सच मान कर देश की आधी आबादी जिन्दगी जी रही है। और इस जिन्दगी को चलाने वाले नेताओं की कतार सिर्फ बोलती है क्योकि बोल कर वोट पाने का लाइसेंस उन्ही के पास हो और लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है कि जो खूब शानदार बोल सकता है वहीं देश की सत्ता को संभाल सकता है। यानी सारे सवाल उस दायरे में आकर सिमट जाते है जहा 2014 में 10 जनपथ तक जीरो जीरो लगाते हुये करोड़ो के घोटाले – घपले का आरोप नेहरु गांधी परिवार पर नरेन्द्र मोदी लगाकर सत्ता पाते है और 2019 में नरेन्द्र मोदी को चौकीदार चोर है कि उपमा दे कर राहुल गांधी अब परिपक्व नजर आने लगते है क्योकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस कई राज्यो में लौट आती है।

तो सवाल कई है। मसलन, क्या भारत को बनाना रिपब्लिक बनाकर सत्ता पाना ही लोकतंत्र हो चुका है। क्या भारतीय ही भारत को लूट कर गणतंत्र होने का तमगा सीने से लगाये हुये है। क्या भारतीय राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता का मोल भाव सत्ता बनाने या बिगाडने में जा सिमटा है। क्या संविधान को भी सत्ता का और बनाकर सत्ताधारी देश से खेलने में हिचक नहीं रह है। क्या देश में खुली लूट कर देश छोडकर भागना बेहद आसान है क्यों कि सत्ता पाने की तिकडम, चुनाव के तौर तरीके, ही एक ऐसी पूंजी पर जा टिकी है जो इमानदारी से बटोरी नहीं जा सकती और बेइमानी किये बगैर लौटायी नहीं जा सकती। क्या दुनिया में भारत इसलिये आकर्षण का केन्द्र है क्योकि भारतीय बाजार से कमाई सबसे ज्यादा है। या फिर जिस तरह दो जून की रोटी तले आस्था के समंदर में देश के 80 करोड़ लोग गोते लगाते है उसमें दुनिया की कोई भी फिलास्फी फेल होने के बाद भारत आकर आंनद ले सकती है। या फिर भारत धीरे धीरे खुद को उस पुरातन अवस्था में ले जा रहा है जंहा विकसित या विकासशील होने – कहलाने का मार्ग नहीं जाता बल्कि अतीत के गौरवमयी हालातों को धर्म की चादर में लपेट कर सत्ता सुला देना चाहती है। यानी मिजाज लेकतंत्र का हो या परिभाषा आजादी की गढ़ी जाये या फिर आस्था के आसरे राष्ट्रवाद और देश भक्ति के नारे लगाये जाये, भारत कैसे सत्ता की लूट और विज्ञान के आसरे विकसित होने की तरफ ध्यान ही ना दें इसके उपाय भी लगातार खोजे जा रहे हैं। क्योकि शिक्षा – प्रोफेशनल्स – रोजगार को लेकर दुनिया में फैले विदेशियों की तादाद में भारत का नंबर चीन – जापान के बाद आता है। चीनी और जापानी देश लौटते है। नागरिकता छोडते नहीं। अपने देश के लिये काम करते हैं। पर दुनिया में फैले भारतीयों की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये तादाद ना लौटने के लिये बढ़ रही है। तो क्या लोकतंत्र के नाम पर भारत खुद को ही नये तरीके से गढ़ रहा है जहा गांव से रास्ता छोटे शहर। छोटे शहर से बडे शहर। बडे शहर से महानगर। और महानगर से देश छोड कर जाने का रास्ता ही भारत की पहचान हो चुकी है। और जो राजनीति सत्ता देश को चलाने के लिये बैचेन रहती है वह भी अब विदेशी जमीन पर अपने होने का राग गा रही है क्योंकि देश के भीतर का सिस्टम या तो पूंजी पर जा टिका है या पूंजीपतियों पर जो सत्ता को भी गढ़ते हैं और सत्ता के जरीये खुद को भी। फिर सियासत डगमगाने लगे तो देश की नागरिकता छोड भारतीय व्यवस्था पर ही सवाल उठाने से नहीं चुकते। और सत्ता कहती है जय हिन्द !

देश भक्ति की लौ में जलता भारत

यह सेना की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाज़ी को आखिरकार मार गिराया हालांकि इस ऑपरेशन में एक मेजर समेत हमारे चार जांबांज सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए। देश इस समय बेहद कठिन दौर से गुज़र रहा है क्योंकि हमारे सैनिकों की शहादत का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भारत अपने 40 वीर सपूतों को धधकते दिल और नाम आँखों से अंतिम विदाई दे भी नही पाया था, सेना अभी अपने इन वीरों के बलिदान को ठीक से नमन भी नहीं कर पाई थी, राष्ट्र अपने भीतर के घुटन भरे आक्रोश से उबर भी नहीं पाया था, कि 18 फरवरी की सुबह फिर हमारे पांच जवानों की शहादत की एक और मनहूस खबर आई।

पुलवामा की इस हृदयविदारक घटना में सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि वो 40 सीआरपीएफ के जवान किसी युद्ध के लिए नही गए थे। वे तो छुटियों के बाद अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। 'जिहाद' की खातिर एक आत्मघाती हमलावर ने सेना के काफिले पर इस फियादीन हमले को अंजाम दिया। हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए कि पाक पोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी लेता है बल्कि उस सुसाइड बम्बर का हमले के लिए जाने से पहले का एक वीडियो भी रिलीज़ करता है। इंसानियत का इससे घिनौना चेहरा क्या हो सकता है। इससे किसे क्या हासिल हुआ कहना मुश्किल है लेकिन इस घटना ने इतना तो साबित कर ही दिया कि बिना स्थानीय मदद के ऐसी किसी वारदात को अंजाम देना संभव नही था। कहने की आवश्यकता नही कि इस वीभत्सता में कश्मीरियत जम्हूरियत और इंसानियत ने कब का दम तोड़ दिया है। वो घाटी जो जन्नत हुआ करती थी आज केसर से नही लहू से लाल है। वो कश्मीर जो अपनी सूफी संस्कृति के लिए जाना जाता था आज आतंक का पर्याय बन चुका है।

घाटी में आतंक का ये सिलसिला जो 1987 से शुरू हुआ था वो अब निर्णायक दौर में है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवानों के खून की एक एक बूंद और हर आंख से गिरने वाले एक एक आँसू का ऐसा बदला लिया जायेगा कि विश्व इस न्यू इंडिया को महसूस करेगा।

वर्तमान सरकार के प्रयासों से स्पष्ट है कि वो इस बार आरपार की लड़ाई के पक्ष में है और यह सही भी है। क्योंकि देश में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस समय जो देश का माहौल बना हुआ है, वो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज देश की हर आंख नम है, हर दिल शहीदों के परिवार के दर्द को समझ रहा है, हर शीर्ष उस माता पिता के आगे नतमस्तक है जिसने अपना जिगर का टुकड़ा भारत माँ के चरणों में समर्पित किया। हर हृदय कृतज्ञ है उस वीरांगना का जिसने अपनी मांग का सिंदूर देश को सौंप दिया और हर भारत वासी ऋणी है उस बालक का जो पिता के कंधों पर बैठने की उम्र में अपने पिता को कंधा दे रहा है।

ये वाकई में एक नया भारत है जिसमें आज हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही है। यह एक अघोषित युद्ध का वो दौर है जिसमें हर व्यक्ति देश हित में अपना योगदान देने के लिए बेचैन है। कोई शहीदों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई अपनी एक महीने की तनख्वाह दे रहा है। स्थिति यह है कि 'भारत के वीर' में मात्र दो दिन में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हो गई। आज देश की मनःस्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश का बच्चा बच्चा और महिलाएं तक कह रही हैं कि हमें सीमा पर जाने दो हम पाकिस्तान से बदला लेने को बेताब हैं। पूरा देश अब पाकिस्तान से बातचीत नही बदला चाहता है। हालात यह हैं कि पाक से बातचीत करने जैसा बयान देने पर सिद्धू को एक टीवी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो कहीं पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वाले को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। जिस देश में कुछ समय पहले तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के पक्ष में कई राजनैतिक दलों के नेता और मानववादी संगठन इकटठा हो जाते थे, आज वो देश भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज रहा है। टीवी चैनल और सोशल मीडिया देश भक्ति और वीररस की कविताओं से ओतप्रोत हैं। यह नए भारत की गूंज ही है कि अपने भाषणों में हरदम आग उगलने वाले ओवैसी जैसे नेता पहली बार आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं। यह नए भारत की ताकत ही है कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं के छीने जाने पर फारूख अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती जैसे घाटी के नेता शांत हैं। और नए भारत की यह ताकत सिर्फ देश में ही नही दुनिया में भी दिखाई दी जब आतंकवाद की इस घटना पर विश्व के 48 देशों ने भारत को समर्थन दिया। अमेरिका से लेकर रूस ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और वे भारत के साथ हैं।

और यह नए भारत की शक्ति ही है कि आज पाकिस्तान बैकफुट पर है। आज वो अपने परमाणु हथियार सम्पन्न होने के दम पर युद्ध की धमकी नही दे रहा बल्कि इस हमले में अपना हाथ न होने की सफाई दे रहा है। यह नए भारत का दम है कि यह हरकत उसपर उल्टी पड़ गई। दरअसल अमरीका की ट्रम्प सरकार द्वारा अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने के फैसले से आतंकी संगठनों और पाक दोनों के हौसले फिर से बुलंद होने लगे थे। इस समय को उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के मौके के रूप में देखा। क्योंकि सेना की मुस्तैदी और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते वे काफी समय से देश या घाटी में कोई वारदात नही कर पा रहे थे जिससे उन्हें अपने अस्तित्व पर ही खतरा दिखने लगा था और वो जबरदस्त दबाव में थे। उन्होंने सोचा था कि भारत में चुनाव से पहले 'कुछ बड़ा' करके वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे जबकि हुआ उल्टा। क्योकि आज आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान सामाजिक रूप से भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। और रही सही कसर भारत के प्रधानमंत्री के बदला लेने के संकल्प के बाद 14 तारीख से लगातार भारत के हर गली कूचे में गूंजने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों ने उसको मनोवैज्ञानिक पराजय दे कर पूरी कर दी। वो पाक अपनी नापाक हरकतों से विश्व में आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक और राजनैतिक मोर्चे पर आज बेहद बुरे दौर से गुज़र रहा है। अपने दुश्मन की इस आधी पराजय को अपनी सम्पूर्ण विजय में बदलने का इससे श्रेष्ठ समय हो नहीं सकता जब देश के हर बच्चे में सैनिक, हर युवा में एक योद्धा और हर नारी में दुर्गा का रूप उतर आया हो।

डॉ. नीलम महेंद्र

एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण नए औद्योगिक ईकाइयों के 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राज ठाकुर की अध्यक्षता में गत सांय छठी राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। जिसमें लगभग 309.45 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की 16 नई औद्योगिक ईकाइयों को स्थापित करने

व वर्तमान ईकाइयों के विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इन से 1000 से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। इतनी मात्र में निवेश प्रस्ताव आना प्रदर्शित करता है कि आर्थिक मन्दी के बावजूद भी राज्य निरंतर निवेश आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के हरीपुर गांव में मैसर्ज ग्लोबल कालस्टगज को ऑटोमोटिव व मशीन कास्ट आयरन पार्ट्स के निर्माण तथा सोलन जिला की तहसील बद्दी के गांव कारूवाणा में मैसर्ज टाईम टैक्नोप्लास्ट लिमिटेड को पीवीसी डबल तथा सिंगल लूप और वाईप मैटिंगज के निर्माण की नए प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक में सोलन जिला के बद्दी के गांव डामोवाला के मैसर्ज डीएस ड्रिंक्स एण्ड वैबेरेजिज प्राईवेट लिमिटेड यूनिट – 5 को कार्बोनेटिड फूट ड्रिंक्स कार्बोनेटिड सॉफ्ट ड्रिंक्स के निर्माण तथा ऊना जिला के टालीवाल के मैसर्ज जय गुरू जी एन्टरप्राईजिज को पीओपी फिलामैंट (थ्रैड फॉर काईट्स/मांजा) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

प्राधिकरण ने ऊना जिला की हरोली तहसील के सिंघा में क्रिमी का फूड पार्क के शैड नम्बर – 4,5 में मैसर्ज एनईसी रोटो फलैक्स पैकिंग कॉर्पोरेशन को एप्पल जूस कन्सट्रेट के निर्माण तथा सिरमौर जिला के कालाअम्ब के गांव कुण्डला में मैसर्ज एलको स्पिरिट्स प्राईवेट लिमिटेड को देसी शराब तथा आईएमएफएल के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

विस्तार प्रस्ताव में ऊना जिला के हरोली के गौंदपुर जयचन्द गांव में मैसर्ज मोडूलस कॉस्मेटिक्स को सोप, नुडल, लाऊण्डरी सोप, हाईड्रोजिनेटिड रिफाइन्ड पाम आयल फलैक्सिज, रिफाइन्ड, ग्लिसरीन के निर्माण तथा सोलन जिला के बद्दी तहसील के गांव धकड़ू, माजना तथा कत्था में मैसर्ज एरोडाईग वर्धमान टैक्सटाईल लिमिटेड की इकाई को डाइड यार्न डाइड फाईवर के निर्माण, सोलन जिला के बद्दी के झाड़माजरी की मैसर्ज एमफोरस इंक प्लांट नम्बर – 3 तथा 5 ईपीआईपी आईआईए को ट्रैक्टर तथा ऑटो पार्ट्स के निर्माण, सोलन जिला नालागढ़ तहसील की गांव मंझोली में मैसर्ज इण्डियन कार्ड क्लोथिंग कम्पनी लिमिटेड को मैटलिक कार्ड क्लोथिंग, एकूरा कार्ड क्लोथिंग, टोप्स कार्ड क्लोथिंग के निर्माण, सिरमौर जिला के कालाअम्ब के गांव झरोन में मैसर्ज सर्व बॉयोलैबज प्राईवेट लिमिटेड को थियोकोलचिकोसाइड, कोल्चिसिन, पैक्लिटैक्सल,हाईयोसाइन, दस – डीएबी डब के निर्माण, जिला ऊना के मुबारिकपुर के शिवपुर गांव में मैसर्ज एमको इन्डस्ट्री को कास्टिंग आयरन स्टील तथा स्टैनलैस स्टील के वालवज कॉक्स और बॉयलर माउंटिग फिटिग्ज के निर्माण, सोलन जिला के बद्दी के कुंजल गांव में मैसर्ज कमैक्स ऑयल प्राईवेट लिमिटेड को ग्लिसरीन डिस्टिल्ड फैटी एसिड, सोप नुडलज के निर्माण, ऊना जिला की हरोली के बेलाबाथरी गांव में मैसर्ज नायसा मल्टीप्लास्ट को स्टील बोतलज अन्य स्टील उत्पादों, इलैक्ट्रिक टिफीन, इन्सुलेटिड केरी हाउसहोल्ड, आर्टीकल्ज बोतलज, हाउसहोल्ड आटर्किल इत्यादि के निर्माण, ऊना जिला के अम्ब के शिवपुर माहल गांव में मैसर्ज लिवगार्ड बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड यूनिट – 1 को इलैक्ट्रिक व्हीकल्ज कवरिंग इलैक्ट्रिक बाईक, इलैक्ट्रिक रिक्शा तथा पिकअप ट्रक, वोल्टेज सटैबलाईजर तथा ट्रांस्फार्मर इन्वर्टर/यूपीएस लीड एसिड बैटरी इत्यादि के निर्माण, सोलन जिला की बद्दी के लेही गांव में मैसर्ज लीव गार्ड बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड इकाई – 3 को बैटरी प्लेटस तथा लीड एसीड बैटरी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, प्रधान सचिव आबकारी एवं काराधान जे.सी. शर्मा, सचिव वित्त अक्षय सूद, श्रम आयुक्त एस.एस. गुलेरिया, एचपीएसईबी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक जे.पी. काल्टा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इएनसी विक्रांत सुमन व अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस को दिखाई हरी झंडी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य विधानसभा परिसर से शिमला शहर के लिए इलेक्ट्रिक बस

को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहा कि शिमला शहर में ऐसी अन्य 50 बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन बसों में आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए है और यह बसें प्रदूषण रहित होंगी। यह शिमला शहर के समृद्ध और स्वच्छ वातावरण की रक्षा के लिए एक कारगर कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह बस यात्रियों को प्रदूषण रहित, शोर मुक्त और आरामदायक यात्रा का आनंद देगी।

परिवहन मंत्री गोबिन्द ठाकुर, मुख्य सचिव बी.के.अग्रवाल, मुख्य सचिव परिवहन जे.सी.शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुंडू, एमडी एचआरटीसी डॉ. संदीप भटनागर सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वर्ष 2019-20 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर व्यय होंगे 2543 करोड़ रुपए:डॉ.सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ.राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में कमजोर वर्गो एवं पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019 – 20 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2543 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। डॉ.सैजल सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत जुब्बड़ में मैसर्ज पेरूवाल प्राईवेट लिमिटिड द्वारा क्षेत्र के कमजोर वर्गो के 100 परिवारों को 1000 रुपए प्रतिमाह की पैंशन के चैक वितरित करने के उपरान्त उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर जम्मू – कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धाजंलि अर्पित की गई।

डॉ. सैजल ने कहा कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार संतुलित विकास एवं धन के समुचित उपयोग पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम बजट में जहां 30 नई योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गो के कल्याण की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी वहीं वित्त वर्ष 2019 – 20 के बजट में सतत एवं सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रथम अप्रैल, 2019 से सामाजिक सुरक्षा पैंशन 750 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 850 रुपए की जाएगी। 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1300 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर 642 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। गत वर्ष इन योजनाओं पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

उन्होंने कहा कि प्रथम अप्रैल, 2019 से सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त कर रही सभी विधवाओं को हिम केयर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इन सभी महिलाओं को बिना कोई प्रीमियम दिए 05 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ उठाएं।

डॉ. सैजल ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है। प्रदेश सरकार इस और विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने क्षेत्र के कमजोर वर्गो को 1000 रुपए प्रतिमाह पैंशन प्रदान करने के लिए मैसर्ज पेरूवाल प्राईवेट लिमिटिड प्रबन्धन की सराहना की।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनीं तथा अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए।

मैसर्ज पेरूवाल प्राईवेट लिमिटिड के निदेशक हरबिन्दर सिंह पुरेवाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कम्पनी द्वारा क्षेत्र की 15 पंचायतों के 100 परिवारों को 1000 रुपए प्रतिमाह पैंशन उपलब्ध करवाई जाएगी।

कम्पनी के अध्यक्ष गुरबचन सिंह ने कहा कि अगले माह से यह पैंशन लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में आएगी।

ग्राम पंचायत गुल्हाड़ी के प्रधान तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य मदन मोहन मेहता, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुन्दरम ठाकुर, लाज किशोर वर्मा, ग्राम पंचायत धर्मपुर के प्रधान सुशील शर्मा, क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ भाजपा तथा भाजयुमो नेता, तहसीलदार कसौली कपिल तोमर, अन्य अधिकारी तथा कम्पनी के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मण्डी महा शिवरात्रि के लिए प्रदेश के कलाकारों का चयन ऑडीशन से

शिमला/शैल। प्रदेश के मण्डी में आयोजित किए जाने वाले महा शिवरात्रि महोत्सव – 2019 की सांस्कृतिक सन्धयाओं के लिए इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों के कलाकारों का चयन ऑडीशन द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि कलाकारों के ऑडीशन 23 से 26 फरवरी, 2019 तक मण्डी शहर के पड्डल मैदान स्थित टेबल टेनिस हॉल में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कलाकार अपने आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर, ई – मेल के माध्यम से अथवा फैक्स द्वारा 25 फरवरी, 2019 तक प्रेषित कर सकते हैं। फैक्स पर आवेदन दूरभाष संख्या 01905 – 225211 पर तथा ई – मेल पर adcmandi@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रदेश के अन्य जिलों से ऑडीशन द्वारा 30 कलाकार चयनित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नृत्य श्रेणी में भी प्रदेश के अन्य जिलों एवं मण्डी जिला से 5 – 5 के समूह अथवा एकल कलाकार चयनित किए जाएंगे। उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे अपने आवेदन 25 फरवरी, 2019 तक भेजना सुनिश्चित बनाएं।

मिस्ड कॉल से जानें अपना बैंक बैलेंस, केसीसी बैंक ने शुरू की नई सेवा

शिमला/शैल। आपका खाता यदि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित में है और आपको खाते का बैलेंस जानना है तो अब बैंक जाकर पास बुक प्रिंट करवाने अथवा एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। यह काम अब आप अपने मोबाईल से भी कर सकते हैं। कांगड़ा केंद्रीय बैंक सीमित के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ने ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सेवा शुरू की है। इससे आप कभी भी खाते का बैलेंस जान सकते हैं। बस आपको बैंक में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से बैंक के मोबाइल नंबर 9580079717 पर मिस्ड कॉल करनी होगी। बैंक बैलेंस की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल करने पर ही प्राप्त होगी। मोबाइल नंबर 9580079717 पर ग्राहक की कॉल एक रिंग के बाद स्वयं कट जाएगी और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ग्राहक के बचत खाते का बैलेंस एसएमएस से प्राप्त होगा। विनय कुमार ने कहा कि केसीसी बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवाएं एवं सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इससे पहले ग्राहकों के पास बैंक बैलेंस पता करने के लिए बैंक जाकर पास बुक प्रिंट करवाने या एटीएम जाकर मिनी स्टेटमेंट निकालवाने के विकल्प थे। नई सुविधा से ग्राहकों को बड़ी सहुलियत होगी और उनके समय की भी बचत होगी।

कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की पांचवी बैठक आयोजित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी गठित करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में गत सांय आयोजित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की पांचवी बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुख्य फलैगशिप कार्यक्रम है और प्रदेश सरकार भी राज्य के युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित बनाने के लिए वचनबद्ध है ताकि उन्हें उद्योगों के मांग के अनुरूप तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि हि.प्र. कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-2023 के बीच 65,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2880 से अधिक युवाओं को व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रशिक्षण दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 12 राजकीय महाविद्यालयों में व्यावसायिक स्नातक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 10 महाविद्यालयों में स्नातक के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए ग्रेजुवेट एडऑन प्रोग्राम आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 560 युवाओं का नामांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगारन्मुखी हो। इस पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध हो।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला समन्वयकां के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए ताकि निगम के कार्य का संचालन सही प्रकार से किया जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि निगम की राज्य फलैक्सी समझौता ज्ञापन के तहत औद्योगिक ईकाइयों जैसे सैक्टर स्किल कांउसिल के तहत 4000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है।

कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक रोहन चन्द ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, प्रधान सचिव आबकारी एवं काराधान जे.सी. शर्मा, राज्य समन्वयक नवीन शर्मा, सचिव समान्य प्रशासन डॉ. आर. एन. बत्ता, सचिव वित्त अक्षय सूद, सचिव वित्त के.के. पन्त, श्रम आयुक्त एस.एस. गुलेरिया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वरिष्ठ प्रमुख जय कान्त सिंह व अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा रिपोर्ट ग्रामीण-2018 हिमाचल प्रदेश को किया जारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने असर (एएसइआर) 2018 द्वारा देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और प्रतिनिधि नमूनों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेश रिपोर्ट (रूरल) हिमाचल प्रदेश 2018 को जारी किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थी भाषा व गणित में देशभर में उच्च स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सीखने का स्तर (लरनिंग लेबल) निजी स्कूलों से बेहतर है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रदेश के 99.7 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय सुविधा है और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन प्रतिशत 99.6 प्रतिशत है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पन्त, निदेशक शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, असर के निदेशक डॉ. विलियम वाधवा और प्रथम के सीईओ डॉ. रूकमनी बेनर्जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया सात नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई-डिस्ट्रिक परियोजना के अंतर्गत

शिमला नगर निगम की सात नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। शुरू की गई ऑनलाईन सेवाओं में बिजली, पानी बिल भुगतान, संपत्ति कर भुगतान, पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन, बिजली के एनओसी के लिए आवेदन, कैनोपी के लिए आवेदन और मलबे की डम्पिंग की अनुमति के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सात सेवाओं के शुभारंभ के साथ अब कुल 59 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आरंभ कर दिया गया है और राज्य सरकार वित्त वर्ष 2019-2020 में 136 अन्य सेवाओं को भी आरंभ करेगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को ऑनलाईन बिल भुगतान व एन.ओ.सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को डिजीलॉकर के माध्यम से राशन कार्ड व परिवार नकल रजिस्टर सम्बन्धी दस्तावेजों की उपलब्धता का भी शुभारंभ किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सहयोग से इन सेवाओं को आईटी विभाग द्वारा दस दिनों के भीतर एकीकृत किया गया है। अब राज्य के नागरिक अपना डिजीलॉकर खाता इंटरनेट बेबसाइट http://digilocker.gov.in या मोबाइल फोन पर एन्ड्रॉइड और आईओएस के लिए ऐप डाउनलोड कर बना सकते हैं। एक बार खाता बन जाने के बाद आधार नंबर लिंक करने के उपरांत डिजीलॉकर पर उपलब्ध सूची से उपरोक्त विभागों का चयन करके दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में 18,39,865 राशन कार्ड तथा 16,91,275 परिवार पंजीकृत हैं जिन्हें डिजीलॉकर पर जारी किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के लोग अपने डिजीलॉकर खातों के माध्यम से अपने मोबाइलों और कंप्यूटरों पर अपने परिवार के राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की प्रतियां डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने भी डिजीलॉकर के माध्यम से अपना राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर डाउनलोड किया। उन्होंने विभागों के प्रयासों की सराहना की और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिक इन सेवाओं से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेटरों की निजी एपीएन सेवाओं का उपयोग करके हिमाचल प्रदेश राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (हिमस्वान) का डोंगल भी लॉन्च किया। एक निजी एपीएन कन्फिगर्ड सिम विभागीय उपभोक्ता को सुरक्षित, समर्पित चैनल का उपयोग करते हुए इंटरनेट कलाउड पास कर सीधे हिमस्वान तक पहुंचाएगा तथा एसडीसी में ई-ऑफिस, एसएपी, विभागीय जैसे इंटरनेट एपलीकेशन उपलब्ध करवाएगा जो ओपन इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध नही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि ये सभी सेवाएं राज्य के लोगों को तत्काल और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर शिमला नगर निगम कुसुम सदरेट, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, नगर निगम आयुक्त शिमला पंकज राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने गुसान में गायत्री चेतना केन्द्र का किया भूमि पूजन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मैहली के नजदीक गुसान गांव में गायत्री चेतना केन्द्र का 'भूमि पूजन' किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक मूल्यों व

परम्पराओं को आगे बढ़ाने में सराहनीय कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा और भौतिकतावादी वर्तमान युग में नैतिक मूल्य और परम्पराएं तेज गति से क्षीण हो रही है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार जैसी संस्था सदियों पुरानी परम्पराओं और मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। ताकि भारत एक बार फिर 'विश्व गुरू' बन सके। उन्होंने कहा कि केवल वही समाज उन्नति करते हैं जो अपनी संस्कृति और परम्पराओं का सम्मान करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केन्द्र समाज में समृद्ध परम्पराओं व मूल्यों को विकसित करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की समृ सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश में 'दूसरी राजभाषा' का दर्जा देने का निर्णय लिया है। दजय राम ठाकुर ने गायत्री परिवार के गायत्री चेतना केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पांडिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि गायत्री परिवार एक गैर राजनीतिक संगठन है जो विश्व शांति और भाईचारे के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महान राष्ट्र की समृद्ध परम्पराओं, संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित बना रहा है।

नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, हिमाचल गायत्री परिवार के प्रमुख वी.के. भटनागर, उपायक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक शिमला ओमापति जमवाल व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

शिमला/शैल। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला के तत्वावधान में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर शिमला नगर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से आए अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। आकाशवाणी केंद्र शिमला के कलाकारों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान के प्रभारी निदेशक डॉ. जगदेव शर्मा ने स्वागत उदबोधन प्रस्तुत किया। मुख्य आयकर आयुक्त प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और समारोह में विगत तीन वर्षों के लिए विविध कार्यालयाध्यक्षों को राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपने करकमलों से सम्मानित किया । इस अवसर पर हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव नराकस शिमला नीना मल्होत्रा ने राजभाषा हिंदी की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कार्यकारी सहायक निदेशक अनिल त्रिपाठी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मंच संचालन दूरदर्शन शिमला की कार्यक्रम निष्पादक धारा सरस्वती द्वारा किया गया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

जयराम सरकार ने प्रचार-प्रसार पर खर्च किये 6,64,44,215 रू. मीडिया पॉलिसी पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हर सरकार अपने काम काज और अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती है यह उसका अधिकार और कर्तव्य दोनों ही है। इसी के लिये सरकार अपनी मीडिया पॉलिसी बनाती है। इस काम को अंजाम देने के लिये सरकार का सूचना एवम् जन संपर्क विभाग काम करता है। विभाग और सरकार को सलाह और सहायता देने के लिये मीडिया सलाहकार तक नियुक्त किया जाता है। सरकार के प्रचार प्रसार पर सरकारी कोष से खर्च किया जाता है। इस कोष का खर्चा केवल अपनी पंसद और न पंसद के आधार पर ही खर्च न किया जाये और इसके लिये वाकायदा ठोस नीति बनाई जाये ऐसे निर्देश अदालत तक से भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन इन निर्देशों की अनुपालना शायद ही कोई सरकार करती है। यहां तक की सरकार अपनी ही नीतियों का अनुसरण नही करती है ऐसा भी अकसर सामने आता है।

सरकार अपने काम काज और नीतियों का प्रचार करती है लेकिन यह नीतियां किसके लिये होती है? सरकार किसके लिये काम करती है? यदि इन बिन्दुओं पर विचार किया जाये तो यह निश्चित और स्वभाविक है कि यह सब कुछ प्रदेश की जनता के लिये ही किया जाता है और इसी जनता के पास वह जवाब देह होती है। जब जनता को उसके काम में कुछ कमीयां नजर आती हैं। जब जनता को लगता है कि जो कुछ वायदा किया गया था और जो कुछ प्रचारित किया गया है वह सब कुछ हकीकत से दूर है तब जनता वक्त आने पर उस सरकार को नकार देती है क्योंकि जनता सारी हकीकत को अपनी नंगी आंख से देख रही होती है। यही कारण है कि सैंकड़ों अवार्ड लेने के बाद भी सरकारें हार जाती हैं। बलिक जिन लोगों ने यह अवार्ड दिये होते हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी आंच आती है।

लेकिन सरकारों में सच सुनने जानने की हिम्मत नही होती है। इसलिये जो समाचार पत्र सरकार को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ हकीकत दिखाते हैं उन्हें विरोधी मान लिया जाता है और उनकी आवाज को दबाने के प्रयास किया जाता है और इस प्रयास की कड़ी होता है विज्ञापन। सरकार विज्ञापन बन्द कर देती है या कम कर देती है। ऐसा करने पर बहुत सारे समाचार पत्र सरकार की आरती उतारना ही पंसद करते हैं। क्योंकि जनता उनके सरोकारों में सबसे पीछे चली जाती हैं जबकि एक समाचार पत्र की सफलता उसके पाठक से मिली प्रशंसा होती है सरकार से मिला विज्ञापन समाचार पत्र का आंकलन पाठक उसकी सामग्री से कर लेता है। लेकिन यह प्रचार-प्रसार पर किया जाने वाला खर्च भी तो आम आदमी का पैसा है और इस नाते उसे यह जानने का पूरा हक हासिल है कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है किस समाचार पत्र को क्या दिया जा रहा है और इस पत्र की प्रदेश में क्या प्रसांगिता है। इस परिप्रेक्ष्य में पाठकों के सामने वह सूचना रखी जा रही है जो सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के प्रश्न के उत्तर में सामने आयी है। इस सूची से पाठक यह जान सकते हैं जिन समाचार पत्रों को सरकार ने विज्ञापन जारी किये हैं उनमें से वह कितनों को जानते और पढें हैं। कितनों को सोशल मीडिया साईट पर भी देखा है। क्योंकि अब प्रिन्ट के साथ सोशल साईट भी अनिवार्य कर दी गयी है।

Daily Newspapers

Sr. No.	Name of Newspaper	Amount (in Rs.)
1	Punjab Kesari (Delhi)	445959
2	Mail Today	311776
3	The Hindu	673791
4	Rashtriya Sahara	61367
5	Vir Arjun	25482
6	Hindustan	321881
7	Millennium Post	50960
8	Statesman	362347
9	New Indian Express	63601
10	Aaj Samaj	436508
11	The Tribune	2215027
12	Divya Himachal	1721726
13	The Hindustan Times	1218042
14	The Indian Express	565993
15	The Times of India	560217
16	Daily Post	218479
17	The Pioneer	435187
18	Business Standard	346035
19	Amar Ujala	2046407
20	Punjab Kesari	2782820
21	Dainik Bhaskar	1373594
22	Jansatta	192097
23	Dainik Tribune	226646
24	Naya Lok Yug	254489
25	Yugmarg	309091
26	Desh Pyar	15000
27	Arth Prakash	275425
28	Dainik Jagran	1027421
29	Dainik Savera	1527430
30	Ajit Samachar	398398
31	Uttam Hindu	653413
32	Hindi Milap	228346
33	Himachal Dastak	1084160
34	Aapka Faisla	564577
35	Dainik Nyaya Setu	290299
36	Himachal Sewa	309353
37	Bhartendu Shikhar	193062
38	Hind Janpath	400584
39	Himachal Times(E)	341131
40	Pehli Khabar	138263
41	Navodaya Times	239052
42	Naya India	206928
43	Nav Bharat Times	395316
44	Action India	263912
45	Viksit Bharat Samachar	105587
46	Dainik Jagran Delhi	71,205
47	Shah Times	13,897
48	Amrit India	14,439
49	Jagmarg	20,000
50	Lokmat Uday	20,000
51	Jan Kaal Sandesh	20,000
Total		**26036720**

Weekly Newspapers

Sr. No.	Name of Newspaper	Amount (in Rs.)
1	Himvanti Paonta.	188000
2	Himachal Tribune, Shimla	132000
3	Monal Times,Shimla	140000
4	Himalaya Times, Shimla	120000
5	Shiwalik Patrika, Una	188000
6	Vir Anand, Shimla	188000
7	Him Derishti, Akri	190800
8	Tiranga Hindustan, Paonta	104000
9	Himalayan Dawn, Solan	152000
10	Gram Parivesh, Shimla	224433
11	Hills Guardian, Shimla	188000
12	Him Kisan, Shimla	220000
13	Jan Kiran, Shimla	237000
14	Surya Kamal, Shimla	180000
15	Himachal Darpan, Shimla	75588
16	Jago Himachal, Shimla	132000
17	Aap Ka Saamna, Shimla	60732
18	Himachal Janta, Shimla	94215
19	Girijan Samaj, Shimla	82992
20	Girinder, Shimla	60693
21	Him Bhasha, Shimla	22800
22	Himachal Ki Pukar Shimla	93168
23	Himachal Reporter, Palampur.	100660
24	Himalaya Surya, Shimla	44928
25	Jai Himachal, Shimla	121824
26	Parbat Ki Goonj, Shimla	22800
27	Patan Samachar, Shimla	65318
28	Shail Samachar, Shimla	90542
29	Shoolini Samachar Shimla	139536
30	Himachal Surkhiyan, Shimla	48720
31	Jago World, Shimla	154958
32	Bakhbar Connect, Shimla	119574
33	Shimla Today, Shimla	76748
34	Democracy Himachal, Shimla	132000
35	Divya Prabhat, Shimla	85242
36	Mangal Udaya, Shimla	69300
37	Himachal Abhi Abhi, Kangra	117120
38	Parchand Himachal, Shimla	76280
39	Amar Jawala, Mandi	108151
40	Friday Times, Shimla	66513
41	Shimla Post, Shimla	91875
42	Aadarsh Himachal, Shimla	46242
43	Shimla Panorama, Shimla	94800
44	Hamirpur Patirka	7875
45	Hello Himachal	31500
46	Himachal This Week	50400
47	Himachal Uday	7875
48	Kids Bulletin	48168
49	Focus Himachal	11025
50	Nayar Himachal	7875
51	Him Dastkar	7875
52	Shiwalik Times	7875
53	Himachal News	11025
54	Him Manas	7875
55	Prithvi Lok	7875
56	Janwaqta	7875
57	Himalayan Update	11025
Total		**5173695**
Grand Total of Dailies & Weeklies		**31210415**

इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया के माधयम से किए प्रचार एवं प्रसार केव्यय का प्रति एजैंसी विवरणः

Sr. No.	Name of TV/Radio channel/ Cable TV Network	Expenditure incurred (in Rs.)
1.	DDK Shimla	2,88,880-00
2.	News18 (Punjab Haryana Himachal)	7,41,783-00
3.	ZEE (Punjab Haryana Himachal)	11,34,812-00
4.	Khabrein Abhi Tak	2,45,960-00
5.	MH- One	2,72,298-00
6.	TV 100	8,19,059-00
7.	R.C.Communication (HP24x7) Mandi	1,17,812-00
8.	Shimla Satellite Pvt.Ltd. (Channel-9)	2,12,741-00
9.	Good Media Pvt.Ltd. (City Channel Shimla)	1,90,841-00
10.	AIR Shimla	10,52,550-00
11.	FM Shimla	6,59,662-00
12.	FM Hamirpur	6,59,662-00
13.	FM Dharamshala	6,59,662-00
14.	Radio Mirchi	3,53,230-00
15.	Radio Dhamaal	2,81,389-00
16.	BIG FM	2,65,427-00
17.	RED FM	75,473-00
18.	MY FM	79,827-00
19.	Vritti Solutions Pvt.Ltd., Pune (through passenger's information system installed at 16 HRTC Bus Stands throughout the State)	13,62,632-00
20.	Janta TV	3,16,476-00
21.	www.a4applenews.com	11,800/-
22.	www.himshimlalive.com	11,800/-
23.	www.shivaliktimes.com	11,800/-
24.	www.sunpost.in	11,800/-
25.	www.himnewspost.com	11,800/-
26.	www.reporterseye.com	11,800/-
27.	www.aadarshhimachal.com	11,800/-
28.	www.a4applenews.com	11,800/-
29.	www.himshimlalive.com	11,800/-
30.	www.shivaliktimes.com	11,800/-
31.	www.sunpost.in	11,800/-
32.	www.himnewspost.com	11,800/-
33.	www.reporterseye.com	11,800/-
34.	www.sanjayuvaach.in	11,800/-
35.	www.newsviewspost.com	11,800/-
36.	www.news24x365.com	11,800/-
37.	www.dnewsnetwork.in	11,800/-
38.	www.unn-hp.org	11,800/-
39.	www.northindiatimes.com	11,800/-
40.	www.srikhandtimes.com	11,800/-
41.	www.divyalive.com	11,800/-
42.	www.himachalabhiabhi.com	11,800/-
43.	www.hillpost.com	11,800/-
44.	www. himsatta.com	11,800/-
45.	www.todaytimes.co.in	11,800/-
46.	www.himachaltribune.com	11,800/-
47.	www.himvani.com	11,800/-
48.	www.samacharfirst.com	11,800/-
49.	Shree Balaji Media Innovations Pvt Ltd.	30,000/-
Total		**1,01,50,576/-**

17 करोड़ की मुख्यमन्त्री राहत से सिराज को मिले 3 करोड़

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री राहत कोष एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी व्यक्ति की सहायता की जा सकती है। इसकी सहायता की पात्रता के लिये कोई बड़े कड़े नियम नही है जैसा की अन्य योजनाओं में होता है। इसके तहत दी गयी सहायता को किसी भी तरह से किसी अदालत में चुनौती नही दी जा सकती है। इसमें केवल यही देखा जाता है कि जिस दिन यह सहायता मांगी जाती है उस दिन मुख्यमन्त्री राहत कोष में धन उपलब्ध होना चाहिये और सहायता मांगने वाले के पास उस समय और कोई साधन उपलब्ध नही था। मुख्यमन्त्री राहत कोष से सामान्यत:आवदेन संबंधित एसडीएम कार्यालय के माध्यम से भेजे जाते हैं ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके की सहायता मांगने वाला सही में इसका पात्र है। वैसे नियमों में ऐसी कोई बंदिश नही है क्योंकि यह सहायता मुख्यमन्त्री के अपने विवके पर निर्भर करती है और मुख्यमंत्री किसी भी ऐसे आग्रह को अस्वीकार भी कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष शुद्ध रूप से केवल सरकारी धन ही नही होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को इसमें योगदान दे सकता है और मुख्यमंत्री अपने विवके से इसमें से कोई भी आंवटन कर सकते हैं। इस वित्तिय वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष से 27 दिसम्बर 2017 से 15 जनवरी 2019 तक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 17,34,51,949 रूपये की सहायता दी गयी है। इसमें मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज में 3,03,17,140 रूपये की सहायता दी गयी है।

क्र. सं.	विधाानसभा क्षेत्र का नाम	वितरित की गई राशि
1.	बिलासपुर	9,59,500
2.	घुमारवीं	23,23,100
3.	झण्डूता	12,63,500
4.	श्रीनैनादेवी जी	28,34,500
5.	भरमौर	9,48,000
6.	भटियात	8,25,100
7.	चम्बा	7,80,100
8.	चुराह	3,14,100
9.	डलहौजी	8,40,000
10.	बड़सर	15,04,100
11.	भौरन्ज	26,65,100
12.	हमीरपुर	6,14,800
13.	नदौन	16,38,200
14.	सुजानपुर	18,54,800
15.	बैजनाथ	14,61,789
16.	देहरा	33,27,300
17.	धर्मशाला	9,94,000
18.	फतेहपुर	3,75,200
19.	इन्दौरा	21,44,800
20.	जैसिंहपुर	16,30,300
21.	जसवॉ परागपुर	91,24,300
22.	ज्वालामुखी	25,50,300
23.	ज्वाली	12,56,200
24.	कांगड़ा	15,83,200
25.	नगरोटा	19,44,000
26.	नूरपुर	25,23,400
27.	पालमपुर	16,65,900
28.	शाहपुर	11,41,200
29.	सुलह	78,04,563
30.	किन्नौर	22,43,276
31.	आनी	34,09,711
32.	बन्जार	15,94,000
33.	कुल्लू	6,73,000
34.	मनाली	48,84,100
35.	लाहौल एवं स्पिति	13,43,000
36.	बल्ह	24,91,000
37.	द्रंग	19,51,334
38.	धर्मपुर	36,39,455
39.	जोगिन्द्रनगर	35,05,513
40.	करसोग	39,64,422
41.	मण्डी	18,68,600
42.	नाचन	44,49,500
43.	सरकाघाट	25,76,816
44.	सिराज	3,03,17,140
45.	सुन्दरनगर	38,86,100
46.	चौपाल	32,86,059
47	जुब्बल-कोटखाई	29,27,300
48.	कसुम्पटी	12,94,400
49.	रामपुर	15,02,300
50.	रोहडू	34,75,530
51.	शिमला (शहरी)	14,29,000
52.	शिमला (ग्रामीण)	18,03,300
53.	ठियोग	15,92,971
54.	नाहन	23,66,100
55.	पच्छाद	17,41,000
56.	पौंटा-साहिब	30,04,200
57.	शिलाई	20,86,100
58.	श्रीरेणुका जी	19,63,000
59.	अर्की	11,49,500
60.	दून	4,05,000
61.	कसौली	14,65,000
62.	नालागढ़	5,28,200
63.	सोलन	12,07,600
64.	चिन्तपुर्णी	16,43,300
65.	गगरेट	7,99,870
66.	हरोली	10,96,000
67.	कुटलेहड़	26,57,800
68.	ऊना	23,40,100
कुल		**17,34,51,949/-** रूपये (सतरह करोड़ चौंतीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ उन्चास रूपये केवल)